हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्षः 11 अंकः 173 लखनऊ, बुधवार 18 फ़रवरी 2026 पृष्ठः 04 मूल्यः 01 रूपये

श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आएं अखिलेशः मुख्यमंत्री

2027 में उत्तर प्रदेश में फिर बनेगी भाजपा नेतृत्व की डबल इंजन सरकारः योगी आदित्यनाथ

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए आगे आने की सलाह दी है। इटावा में निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर के संभावित निमंत्रण पर उन्होंने कहा कि यदि अखिलेश यादव शुद्ध नीयत से यह मंदिर बनवाते तो मैं अवश्य जाता, लेकिन नीयत साफ नहीं है। फिर भी मैं उनको बधाई दूंगा कि देर आए–दुरुस्त आए, आखिर मंदिर बनवा रहे हैं। अब वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आगे आएं, लोग प्रशंसा करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को एक निजी चौनल के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे। इस मौके पर सीएम योगी ने साफ शब्दों में ऐलान किया कि 2022 से अधिक सीटें पाकर 2027 में डबल इंजन की भाजपा सरकार फिर सत्ता में आएगी।

2027 में फिर बनेगी भाजपा नेतृत्व की सरकार

सीएम योगी ने कहा कि 2027 को लेकर कोई शक नहीं है। 2022 से अधिक सीट मिलेंगी और 2027 में फिर भाजपा नेतृत्व की डबल इंजन सरकार बनेगी। डबल इंजन सरकार ने यूपी को ट्रिपल–टी (टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट व ट्रांसफॉर्मेशन) से जोड़ा है और वह 2027 में धूम–धड़ाके के साथ फिर से आएगी। कांग्रेस व राजद की जो दुर्गति बिहार में हुई है, 2027 में वही दुर्गति कांग्रेस व सपा की उत्तर प्रदेश में तय है। सीएम ने मीडियाकर्मियों से कहा कि आप सभी 75 जनपदों, 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाइए, आम जनता वर्तमान सरकार की वकालत करती नजर आएगी।

राममंदिर के साथ रामराज्य की वास्तविक अवधारणा को धरातल पर उतारा

एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी को उसकी पहचान वापस दिलाना सबसे बड़ा अचीवमेंट है। यूपी का नौजवान अब पहचान का मोहताज नहीं। किसान खुशहाल है और श्रमिक स्वावलंबन के साथ अपने जनपद–क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं और यूपी आर्थिक उन्नति के नित नए सोपान प्राप्त कर रहा है। यही रामराज्य है। बिना भेदभाव हर तबके को उसका हक प्राप्त हो रहा है। भगवान राम की जन्मभूमि पर राममंदिर का निर्माण रामराज्य की अवधारणा पर ही आधारित है। हम केवल मंदिर बना देते और यह बदलाव करके नहीं दिखाते तो यह भगवान राम की अवज्ञा होती। हम लोगों ने रामराज्य की वास्तविक अवधारणा को धरातल पर उतारने का कार्य किया। यह डबल इंजन सरकार की ताकत है, जो कहा है, वह करके दिखाया है। आगे भी जो कहेंगे, करके दिखाएंगे।

महाराज सुहेलदेव का विरोध और गाजी का मेला लगाते हैं सपाई

सीएम योगी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर को अपवित्र करने वाले और अयोध्या में श्रीराम मंदिर पर पहला आतंकी हमला करने वाले गाजी को उसके पापों की सजा महाराज सुहेलदेव ने दी थी। लेकिन सपा के लोग महाराज सुहेलदेव का गुणगान करने के बजाय गाजी का नाम लेते हैं, उसका मेला लगाते हैं। ये लोग महाराज सुहेलदेव के स्मारक का विरोध करते हैं। हमें गर्व है कि भाजपा सरकार ने बहराइच में महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक और आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय का निर्माण किया।

परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीडीए) के चेयरमैन हैं अखिलेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के पीडीए को अवसरवाद का दूसरा नमूना बताया। बोले कि पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह एक परिवार के विकास के लिए गठित अवसरवादी अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन अखिलेश, शिवपाल सीईओ और रामगोपाल यादव वाइस चेयरमैन होंगे। उनके पास महाभारत के सारे रिश्ते हैं, बाकी अन्य भाई–भतीजों को भी इसमें स्थान मिलेगा।

देश राहुल गांधी को और प्रदेश अखिलेश यादव को गंभीरता से नहीं लेता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसकी जैसी दृष्टि, वैसी सृष्टि। इन लोगों को कोई नहीं समझा सकता, इनकी दृष्टि देश व प्रदेश के लिए हमेशा नकारात्मक रही है। राहुल गांधी को देश और अखिलेश यादव को यूपी गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस किसी को भी नेता प्रतिपक्ष बना सकती थी। सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए परिवारवादी पार्टी ने राहुल जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी। जब जहाज डूबता है तो कैप्टन भी वही व्यक्ति बनता है, जो उसे आसानी से डुबो सके, इसलिए राहुल जी को कैप्टन बनाया गया।

अखिलेश संघ की शाखाओं में जाएंगे तो जल्दी जागना सीख जाएंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाकर सामान्य आचार व नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। अखिलेश यादव 12 बजे सोकर उठते हैं, वे संघ की शाखा में जाएंगे तो जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। समय पर जागेंगे तो यह उनके हित में होगा और जिस पारिवारिक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, उसका भी नाम बना रहेगा। सीएम योगी ने वंदे मातरम के जिक्र पर कहा कि यह राष्ट्रगीत है, यह आजादी का मंत्र रहा है। इस गीत को गाते–गाते क्रांतिकारियों ने फांसी के फंदे को चूमने में संकोच नहीं किया। राष्ट्र प्रतीकों का अपमान संविधान निर्माताओं, बाबा साहेब व क्रांतिकारियों का अपमान है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व तिरंगा का अपमान राष्ट्रद्रोह है, जिसे भारत स्वीकार नहीं करेगा।

बुलडोजर व ब्रह्मोस एक–दूसरे के पूरक

सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर और ब्रह्मोस एक–दूसरे के पूरक हैं। बुलडोजर यूपी की स्ट्रेंथ का प्रतीक है। हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ–साथ देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को यूपी में स्थापित कर सकते हैं। यूपी की जनता जिसकी अपेक्षा कर रही थी, बुलडोजर उस माफिया प्रवृत्ति को कुचल सकता है। ब्रह्मोस जैसे सेक्टर में भी यूपी में बड़े निवेश हो रहे हैं। यह भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है। किसी ने भारत की आन, बान और शान को लेकर गुस्ताखी करने का प्रयास किया तो दुश्मन को उसके ठिकाने पर जाकर मारेंगे।

'भाग्य नगर' से भयभीत होकर अनर्गल प्रलाप कर रहे ओवैसी

सीएम योगी ने ओवैसी को भी आड़े हाथ लिया। बोले कि यूपी की जनता व डबल इंजन सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि के माध्यम से संदेश दे दिया है। यूपी के बाद भाजपा अब हैदराबाद की तरफ ही रुख करेगी। ओवैसी की पीड़ा इस बात को लेकर है कि कहीं हैदराबाद को भाग्य नगर न बना दिया जाए। भाग्य नगर से भयभीत होकर वे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मुसलमानों का एक पक्ष भले ही उनका समर्थन करता हो, लेकिन यूपी में उनका कोई स्कोप नहीं है। हो सकता है कि अखिलेश उनसे गठबंधन करना चाहते होंगे।

पाकिस्तान की इकॉनमी यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकती

सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान जब मुकाबला नहीं कर पाया तो दुनिया के सामने चिल्लाने लगा। आज भी भारत कोई बड़ा कार्य करता है तो पाकिस्तान दुनिया के मंच पर चिल्लाता है कि मेरी सुरक्षा पर खतरा है। भारत सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है। पाकिस्तान की इकॉनमी यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकती, भारत की बात तो बहुत दूर है।

स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का एलान

रक्षा-तकनीकी क्षेत्रों में भी बड़े समझौते

बीएनई

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को मुंबई में मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिपश के स्तर पर ले जाने का बड़ा फैसला किया। साथ ही दोनों देश ने रक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गईं।

रक्षा और विमानन क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

दोनों नेताओं ने कर्नाटक के वेमागल में एच125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइनश का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई होगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट तक उड़ान भर सकेगा और इसे दूसरे देशों को निर्यात भी किया जाएगा। भारत में हैमर मिसाइल बनाने के लिए बीईएल और फ्रांस की कंपनी सफरान के बीच समझौता हुआ। इसके अलावा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच अधिकारियों की आपसी तैनाती पर भी सहमति बनी।

राजनयिक और आर्थिक बदलाव

भारत और फ्रांस अब हर साल विदेश मंत्री स्तर की वार्ता करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच होराइजन 2047 रोडमैप को लागू करने में मदद मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर, दोनों देश डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट (डीटीएए) के नियमों में बदलाव करने पर सहमत हुए हैं। इससे व्यापार और निवेश में आसानी होगी।

तकनीक, स्वास्थ्य और नवाचार

नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडिया–फ्रांस इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च किया गया। दिल्ली के एम्स (एआईआईएमएस) में स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के इस्तेमाल के लिए एक विशेष केंद्र खुलेगा। साथ ही, एडवांस्ड मटीरियल्स और मेटाबोलिक हेल्थ साइंसेज के लिए भी नए सेंटर बनाने पर सहमति बनी। अंतरिक्ष और विमानन क्षेत्र में कौशल विकास के लिए एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा।

ऐतिहासिक रिश्तों की याद

पीएम मोदी ने मुंबई में राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करते हुए पुराने रिश्तों को याद किया। उन्होंने फ्रांस के मार्सिले शहर का जिक्र किया, जहां प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक पहुंचे थे। उन्होंने वीर सावरकर के साहस को भी याद किया, जो अंग्रेजों से बचने के लिए मार्सिले में समुद्र में कूद गए थे। मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का भरोसा बहुत गहरा है और यह साझेदारी दुनिया में स्थिरता और प्रगति लाएगी।

भविष्य की योजना

भारत में बने पहले एच125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। यह सुविधा नागरिक सेवाओं, आपातकालीन चिकित्सा और यात्री परिवहन के लिए हेलीकॉप्टर तैयार करेगी। दोनों देशों ने डाक विभाग और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन में सहयोग के लिए भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

दुबग्गा में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, शादी की खुशियां मातम में बदलीं, दो को हुई थी सगाई

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। दुबग्गा के मौरा गांव में मंगलवार देर शाम 22 वर्षीय कोमल पाल ने कमरे में पंखे के सहारे दुपट्टे से फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जिस घर में कुछ दिन पहले तक शादी की तैयारियों की चर्चा थी, वहां अब मातम पसरा है। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के मुताबिक मौरा गांव निवासी कोमल ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। मंगलवार रात करीब साढ़े नौ बजे उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। परिजन पडोस में आयोजित एक जन्मदिन पार्टी में गए हुए थे। वापस लौटने पर दरवाजा बंद मिला। काफी आवाज देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का दृश्य देख परिजनों के होश उड़ गए। कोमल पंखे से लटकी मिली। बताया गया कि 2 फरवरी को उसकी सगाई हुई थी और जल्द ही शादी होनी थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन

अचानक इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। ग्रामीणों में चर्चा है कि कोमल आगे पढ़ाई करना चाहती थी, जबकि परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोमल के पिता सुशील पाल ने भी एक वर्ष पहले गांव के बाहर बाग में फांसी लगाकर जान दे दी थी। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक कोमल पर भी आ गई थी। परिवार में चार छोटी बहनें और एक छोटा भाई है। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने बताया कि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। एक साल के भीतर पिता और अब बेटी की असमय मौत ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस आंगन में शहनाई बजने की तैयारी थी, वहां अब सिसकियां गूंज रही हैं।

संक्षिप्त समाचार

जेईई की परीक्षा में फेल होने पर इंटर के छात्र ने दी जान, सुसाइड से पहले घरवालों से की बात, मिली लाश

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। लखनऊ में जेईई परीक्षा में फेल होने से आहत इंटर के छात्र उज्जवल शुक्ला (19) ने बाजाखाला के चित्ताखेड़ा स्थित किराये के मकान में फंदा लगाकर जान दे दी। मंगलवार को उज्जवल का बोर्ड का पहला पेपर भी था। इंस्पेक्टर बाजारखाला बृजेश सिंह ने बताया कि उज्जवल मूल रूप से रायबरेली के गुरुबक्शगंज कृष्णपुर ताला के निवासी थे। वह कुछ समय से बाजारखाला के चित्ताखेड़ा में दो अन्य युवकों के साथ किराये के मकान में रहकर जेईई की तैयारी के साथ इंटरी की पढ़ाई भी कर रहे थे। उज्जवल के साथ किराये पर रहने वाले दोनों युवक अपने–अपने घर गए हुए हैं। उज्जवल के पिता किताब दुकानदार आशुतोष शुक्ला ने बताया कि बेटे ने इस बार जेईई की परीक्षा दी थी। सोमवार को उसका रिजल्ट आना था। शाम करीब सात बजे परिजनों की उज्जवल से बातचीत हुई थी। उसने घरवालों को बताया था कि रिजल्ट की वेबसाइट डाउन चल रही है। इसके बाद परिजनों से उज्जवल से बात नहीं हुई। कुछ घंटे के बाद जब घरवालों ने उज्जवल को फोन किया तो उसका फोन नहीं उठा। उनके पिता ने मकान मालिक से संपर्क किया। रात करीब नौ बजे मकान मालिक उज्जवल के कमरे पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आया।

भारतीय तटरक्षक बल की कार्रवाई, भारत के जलसीमा में मछली पकड़ते 28 बांग्लादेशी को किया गिरफ्तार

बीएनई

कोलकाता। भारतीय तटरक्षक बल ने बंगाल की खाड़ी में एक बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने भारतीय जलसीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ रही एक बांग्लादेशी नाव को पकड़ा है। इस नाव पर सवार 28 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तटरक्षक जहाज आईसीजीएस अमृत कौर ने रविवार को उत्तरी बंगाल की खाड़ी में गश्त कर रहा था। इसी दौरान टीम को संदिग्ध गतिविधि दिखी। जांच में पता चला कि यह बांग्लादेशी नाव भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में बिना अनुमति मछली पकड़ रही थी। यह कार्रवाई विदेशी जहाजों से जुड़े 1981 के कानून के तहत की गई। तटरक्षक दल ने नाव को रोककर उसकी तलाशी ली और जरूरी कागजात मांगे। नाव पर मौजूद लोग कोई भी वैध लाइसेंस नहीं दिखा सके। नाव पर मिले जाल और पकड़ी गई मछलियों से स्पष्ट हुआ कि प्रतिबंधित क्षेत्र में सक्रिय रूप से मछली पकड़ने का काम चल रहा था। तटरक्षक बल ने नाव और सभी 28 सदस्यों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए फ्रेजरगंज बंदरगाह पहुंचाया। तटरक्षक अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई भारत के समुद्री हितों की रक्षा, अवैध मछली पकड़ने पर रोक और क्षेत्र में कार्यरत भारतीय मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय तटरक्षक बल बंगाल की खाड़ी में चौबीसों घंटे सतही और हवाई निगरानी के माध्यम से समुद्री कानूनों को लागू करने और राष्ट्रीय समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सतर्कता बनाए हुए है।

कारोबारी की पत्नी को 12 दिन तक किया डिजिटल अरेस्ट, 90 लाख रुपये ठगे, पुलिस ने गिरोह का पता लगाया

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। ट्रांसपोर्ट कारोबारी की पत्नी को 12 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रख 90 लाख रुपये ठगने वाला गिरोह कई राज्यों में सक्रिय था। इसने अलग–अलग लोगों को लखनऊ पुलिस को मिली है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित के अनुसार, आरोपी मयंक श्रीवास्तव ने बताया कि आर्थिक तंगी के कारण उसने इरशाद से संपर्क किया था। इरशाद ने उसे चालू बैंक खाता उपलब्ध कराने पर कमीशन का

अपना निशाना बनाया था। तमिलनाडु सहित कई राज्यों में इस गिरोह के खिलाफ शिकायतें दर्ज हैं। इसकी जानकारी राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से लालच दिया।

इसके बाद 7 फरवरी को उसे दिल्ली बुलाकर होटलों में ठहराया गया। वहां उसकी मुलाकात इरशाद, आकाश उर्फ मनीष और जीतू उर्फ जीतेंद्र से हुई। आरोपियों ने उसके मोबाइल का पासवर्ड लेकर करोड़ों का साइबर फ्रॉड किया। इसके बदले उसे 10 हजार रुपये दिए और दो लाख रुपये देने का वादा किया। आरोपियों ने मयंक के नाम से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया था। बैंक की चेकबुक और डेबिट कार्ड अपने कब्जे में ले लिए। आरोपी इरशाद ने बताया कि वह तीन प्रतिशत कमीशन पर आकाश उर्फ मनीष और जीतू उर्फ जीतेंद्र के लिए काम करता है। वह खाताधारकों को धन का लालच देकर उनके बैंक खाते, चेकबुक और डेबिट कार्ड ले लेता था। वह व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से गिरोह के अन्य जालसाजों से जुड़ा रहता था। आकाश उर्फ मनीष भी जीतू उर्फ जीतेंद्र के लिए काम करता था और उसे भी साइबर फ्रॉड से मिली रकम का तीन फीसदी कमीशन मिलता था।

जो लोग हिंदू धर्म में लौटें हमें उनका ख्याल रखना होगा, तेज होना चाहिए घर वापसी का काम

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। हिंदू समाज को किसी से भी खतरा नहीं है, लेकिन हमको सावधान रहना होगा। यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने मंगलवार को कही। वह निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने लालच और जबरदस्ती हो रहे मतांतरण पर रोक लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटें, उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। बढ़ती घुसपैठ पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। उन्हें रोजगार नहीं देना है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। उन्होंने कहा एक समय भेद नहीं था, लेकिन समय चक्र के चलते भेदभाव की आदत पड़ गई है, जिसे दूर करना होगा। इस बैठक में सिक्ख,बौद्ध,जैन समाज के साथ ही रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन,

जय गुरुदेव, शिव शांति आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग, संत निरंकारी आश्रम, संत कृपाल आश्रम, कबीर मिशन, गोरक्षा पीठ, आर्य समाज, संत रविदास पीठ, दिव्यानंद आश्रम, ब्रह्म विद्या निकेतन, सहित अलग–अलग वर्गों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

अबला नहीं असुर मर्दिनी है भारतीय नारी

सरसंघचालक ने कहा कि घर–परिवार का आधार मातृशक्ति है। हमारी परंपरा में कमाई का अधिकार पुरुषों को था, लेकिन यह माताएं तय करती थी। मातृशक्ति विवाह के बाद दूसरे घर में आकर सभी को अपना बना लेती है। महिला को हमें अबला नहीं मानना है, वह असुर मर्दिनी है।

जातियां झगड़े का न बने कारण

यूजीसी गाइडलाइन को लेकर किए गए एक प्रश्न के उत्तर में सरसंघचालक ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुक कर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए।

विदेशी शक्तियों के प्रति चेताया

उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन जैसे देशों में बैठे कुछ लोग हमारी सद्भावना के विरुद्ध योजना बना रहे हैं। इससे हमें सावधान रहना होगा। एक दूसरे के प्रति अविश्वास समाप्त करना होगा। एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना होगा।

कानून सभी को मानना है

यूजीसी गाइडलाइन को लेकर किए गए एक प्रश्न के उत्तर में सरसंघचालक ने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए। यदि कानून गलत है तो बदलने का उपाय भी है। जातियां झगड़े का कारण नहीं बनना चाहिए। समाज में अपनेपन का भाव होगा तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जो नीचे गिरे हैं, उन्हें झुक कर ऊपर उठाना पड़ेगा। सभी अपने हैं, यह भाव मन में होना चाहिए। संघर्ष से नहीं, समन्वय से दुनिया आगे बढ़ती है। एक को दबाकर दूसरे को खड़ा करने का भाव नहीं होना चाहिए।

संपादकीय

सावरकर को 'भारत रत्न' देने की मांग को लेकर विवाद

हिंदू विचारक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष और भाजपा के बीच चल रही राजनीतिक बहस को फिर से शुरू कर दिया है, जिससे उनके विचारों, विश्वासों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को लेकर गहरे मतभेद सामने आए हैं। इस मुद्दे ने पहली बार 2019 में बड़ा राजनीतिक तूल पकड़ा, जब भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने सावरकर को भारत रत्न देने की सिफारिश की, जबकि कांग्रेस ने इस पर तीखा हमला किया। यह मांग 2024 में भी फिर से उठी, जब शिवसेना (यू.बी.टी.) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार क्यों नहीं दिया गया। 1883 में नासिक के पास भगूर में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर जन्मे, उनकी शुरुआती जिंदगी उत्तरजीविता और व्यावहारिक चयनों से भरी थी, जैसे कि अंग्रेजों से बातचीत करना और दया याचिकाएं दायर करना, जिसने उनकी जटिल विरासत को आकार दिया। बहुत से लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं क्योंकि उन्होंने अंडेमान की सेलुलर जेल से अंग्रेजों को दया याचिकाएं लिखी थीं। आलोचकों का मानना है कि ये याचिकाएं सालों की कुर्बानी से ज्यादा कमजोरी दिखाती हैं। टॉर्चर खत्म करके नॉर्मल जिंदगी में लौटना इंसान की एक स्वाभाविक इच्छा है। सावरकर ने शहीद बनने की बजाय जिंदा रहना चुना। उनका मानना था कि एक जिंदा क्रांतिकारी, भले ही उसे पाबंद किया गया हो, अंडेमान में मरे हुए हीरो से ज्यादा देश के लिए कर सकता है। सावरकर ने ब्रिटिश सरकार से अपनी याचिकाओं में माफी नहीं मांगी। एक काबिल वकील होने के नाते, उन्होंने कैदियों की स्थिति पर सफाई मांगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस डरावनी जगह पर बिना यह जाने कि उन्हें आम कैदी माना जाता है या पॉलिटिकल कैदी, कैद कर दिया गया था। सावरकर को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हो सकते और उन्हें रत्नागिरी जिंले में ही रहना होगा। सावरकर ने खुद को एक समाज सुधारक के तौर पर पेश किया जो छुआछूत को खत्म करने के लिए समर्पित थे, इस मुद्दे पर उन्होंने बहुत काम किया। हालांकि, उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन के लिए भूमिगत समर्थन भी बनाए रखा। उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन नाम का एक मंदिर बनवाया, जो सभी समुदायों और जातियों के लोगों के लिए खुला था। इस पहल से ऊंची जाति के हिंदू परेशान हो गए। हाल ही में नेहरू आर्काइव से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विनायक दामोदर सावरकर को देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न न देने की सलाह दी थी। यह बात सावरकर की विरासत और इससे पैदा हुए राजनीतिक मतभेदों को लेकर चल रही बहस को और गहरा करती है। जून, 1963 में, नेहरू ने लिखा, ''मैं आपका वह पत्र लौटा रहा हूं जिसमें श्री सावरकर को भारत रत्न देने का सुझाव दिया गया है। हालांकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था लेकिन बाद में वह विवादों में आ गए। मुझे नहीं लगता कि हमें यह सुझाव मानना चाहिए।'' जबकि उस समय के कई सुधारकों ने हिंदू धर्म के ढांचे के अंदर 'अछूतों' को ऊपर उठाने की कोशिश की, सावरकर एक तर्कवादी थे, जो इस ढांचे को पूरी तरह से खत्म करना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने अपनी मान्यताओं के समर्थन के लिए कदम भी उठाए। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनवाया, जो भारत के उन पहले मंदिरों में से एक था, जहां सभी जातियों के लोगों का स्वागत किया जाता था, जिनमें उस समय अछूत माने जाने वाले लोग भी शामिल थे। एक दलित पुजारी को नियुक्त करके और अंतरजातीय खाने और शादी को बढ़ावा देकर, उन्होंने सामाजिक नियमों को चुनौती देने की कोशिश की। उनकी कोशिशों का मकसद अलग–अलग समुदायों के बीच सम्मान जगाना, बराबरी को बढ़ावा देना और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। सार्वजनिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि सावरकर को गिरफ्तार किया गया था और उन पर साजिश का आरोप लगाया गया था। फिर भी, 10 फरवरी, 1949 को, जज आत्मा चरण की अध्यक्षता वाली लाल किले की स्पैशल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। सभी सबूतों की समीक्षा, जिसमें अप्रूवर दिगंबर बडगे की गवाही भी शामिल है, इसमें शामिल कानूनी प्रक्रिया को रेखांकित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, किसी साथी के सबूत को भरोसेमंद होने के लिए स्वतंत्र सबूतों से पुष्टि की जानी चाहिए। प्रॉसिक्यूशन यह देने में नाकाम रहा। सावरकर के पोते, राजेंद्र सावरकर ने केंद्र सरकार से अपने दादा के 'स्वतंत्रवीर' टाइटल को मान्यता देने की मांग की है, यह कहते हुए कि यह मोहनदास कर्मचंद गांधी को दिए गए 'महात्मा' टाइटल जैसा होगा। कई लोग सावरकर को भारत रत्न देने का विरोध करते हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी, लैफ्ट पाध्र्टयां और कुछ विपक्षी ग्रुप शामिल हैं।

राशिफल

मेष :– किसी महत्वपूर्ण कार्य में कुछ कठिनाइयों का अभास होगा। संवेदनशील मन पुरानी मर्मस्पर्शी घटनाओं से ओतप्रोत होगा। पारिवारिक दायित्वों की समयानुकूल पूर्ति हेतु मन चिंतित होगा।

बृषभ :– मनोवांछित सफलता न मिलने से उत्साह में कमी आएगी। भौतिकता से प्रभावित मन अभाव की अनुभूति से दुखित होगा। धैर्यहीनता व परिवर्तनशीलता लक्ष्य से दिग्भ्रमित करेगी।

मिथुन :– परिजनों एवं मित्रों का सनिध्य मन को प्रसन्न रहेगा। कार्य–पेशे में अवरोधित कार्य सार्थक होने के आसार हैं। मांगलिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों में सम्मलित होंगे। महत्वपूर्ण कायरे में आलस्य न करें।

कर्क :– कुछ नये संबंध बनेंगे। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद संभव। कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियों से घिरा मन काल्पनिक आकांक्षाओं से समझौता करने में सक्षम होगा। रोजगार में व्यस्तता रहेगी।

सिंह :– मन खराब विचारों से प्रभावित रहेगा। अतरू उपरोक्त स्वभाव को सुधारें। नई स्थितियों से प्रतिभा का संचार होगा। रोजगार में अपनी कार्यकुशलता व प्रतिभा का जौहर बिखेरेंगे।

कन्या :– वाणी पर नियंतण्ररखते हुए संबंधों को मधुर बनाने की चेष्ठा करें। आत्मबल कुछ महत्वपूर्ण सफलताओं के प्रति आशान्वित करेगा। पूर्वत् स्थिति में सुधार एवं आर्थिक लाभ के आसार हैं।

तुला :– आपकी महत्वाकांक्षाए सफलता की राह पर संघर्ष हेतु प्रेरित करेंगी। अच्छी भावनाएं मकसद को सफल करेंगी। कार्यक्षेत्र में बौद्धिक क्षमता का लाभ उठाएंगे। परिजनों के दुख–सुख के प्रति चिंतित होंगे।

वृश्चिक :– परिश्रम द्वारा आर्थिक क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। समय का पूर्ण उपयोग करें। किसी नयी संवेदना का असर किसी नये रिश्ते को जन्म देगा। मन लक्ष्य के प्रति केंद्रित होने में असमर्थ होगा।

धनु :– परंपराओं एवं संस्कारों के प्रति आस्था बढ़ेगी। निर्थक हीनभाव रखना एवं प्रगतिशील लोगों से ईष्याभाव रखना ठीक नहीं है। किसी अचल सम्पत्ति के क्रय हेतु प्रयत्न तीव्र होगा।

मकर :– किसी महत्वपूर्ण कार्यवश घर से दूर रहना अरुचिकर लगेगा। मिलनसारिता के कारण संबंधों का विस्तार होगा। कमजोर मनोबलवश लक्ष्य के प्रति दृढ़ता का अभाव रहेगा।

कुंभ :– परिवार में खुशीप्रद वातावरण रहेगा। पिछले दिनों उत्पन्न व्यवसायिक अवरोधों का हल ढूंढने हेतु मन केंद्रित होगा। कोई अच्छा अवसर मन को खुश रखेगा। जीवन साथी के साथ मधुरता कायम रखें।

मीन :– प्रयासरत क्षेत्रों में अवरोध तथा दाम्पत्य जीवन में कष्ट संभव। ईरीय आस्था हर स्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। स्वास्य में छोटी–मोटी परेशानियां संभव। धैर्यपूर्वक महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करें।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 : नवाचार से राष्ट्र निर्माण तक

–सुनील कुमार महला

आज का समय तकनीक का समय है, या यूँ कहें कि हम तकनीक के युग में सांस ले रहे हैं। यह तकनीक ही है, जो मनुष्य के जीवन को अधिक सुविधाजनक बना रही है, लेकिन इसके साथ–साथ हमारी सोच, कार्यशैली और आदतें भी आज बदल रही है। कहना ग़लत नहीं होगा कि वर्तमान दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इस परिवर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। तेजी से बदलती भू–राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में आधुनिक तकनीकों के विकास और नवाचार पर विशेष जोर बढ़ा है। आज दुनिया के विभिन्न देश अपनी नीतियों में नई–नई तकनीकों व नवाचारों को शामिल कर अपने देश की विभिन्न पारंपरिक कार्यप्रणालियों को लगातार बदल रहे हैं। विशेष रूप से एआई ने वैश्विक स्तर पर कार्य प्रणाली और मानव भूमिका को गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए आज इसे विकास के लिए अनिवार्य और बहुत ही अहम् माना जा रहा है। इसी संदर्भ में, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एआई शिखर सम्मेलन(इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026; 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक) आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एआई की संभावनाओं, इसकी चुनौतियों, रोजगार पर इसका प्रभाव और आम जीवन में इसके उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज एआई का दायरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कारोबार और रक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि रोजगार पर प्रभाव, जोखिम, डेटा सुरक्षा और पर्यावरणीय असर जैसी चिंताएँ भी इसके कारण सामने आई हैं। विशेष रूप से डेटा केंद्रों में ऊर्जा और पानी की बढ़ती खपत को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए एआई आधारित विकास को सफल बनाने के लिए इसके लाभों के साथ–साथ संभावित खतरों के समाधान पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चलूं कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं और एआई नीति तथा नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरतलब है कि यह समिट भारत मंडपम सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आयोजित हो रही है तथा इसमें 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, साथ ही शीर्ष तकनीकी कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ), शोधकर्ता, नीति–निर्माता और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 800 से अधिक प्रदर्शक, स्टार्टअप, शोध संस्थान और राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं। 16–20 फरवरी तक आयोजित यह एआई शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआइ) के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि उससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल के अनुसार भारत का स्कोर 21.59 है, जबकि अमेरिका का 78.6 और चीन का 36.95 है। इस सूचकांक में भारत कई विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से आगे है। भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ–साथ एआई के क्षेत्र में अग्रणी विकासशील देश भी बन चुका है। इसलिए इस स्तर का वैश्विक आयोजन पहली बार किसी विकासशील देश में होना ऐतिहासिक माना जा रहा है। सम्मेलन में 13 देशों के लगभग 300 पवेलियन वाले एक्सपो का आयोजन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के माध्यम से आम लोगों तक तकनीक के लाभ पहुँचाने, सस्ती तकनीक उपलब्ध कराने और वैश्विक असमानताओं को कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते देश निवेश बढ़ाए, प्रतिभाओं को बनाए रखे और अनुकूल तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करे। वास्तव में, यह समागम विश्व के सबसे बड़े एआई आयोजनों में से एक माना जा रहा है और ग्लोबल साउथ में आयोजित पहली बड़ी एआई शिखर बैठक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों की भूमिका मजबूत होगी। सम्मेलन में एआई आधारित नवाचार, प्रतियोगिताएँ, हैकाथॉन तथा करोड़ों रुपये के पुरस्कार वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे विभिन्न देशों को उद्योग और निवेश के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही एआई के वास्तविक उपयोग (एप्लीकेशन), स्टार्टअप सहयोग और व्यापारिक साझेदारी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यदि हम यहां पर इस समिट के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो, इनमें क्रमशः समावेशी और जिम्मेदार एआई विकास (एआई सभी के लिए और अच्छे के लिए), वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना, विकसित और विकासशील देशों के बीच तकनीकी अंतर को कम करना, सामाजिक–आर्थिक विकास को गति देना (स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, उद्योग और पर्यावरण में सुधार), सुरक्षित, विश्वसनीय और नैतिक एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय नीति संवाद को आगे बढ़ाना तथा भारत को वैश्विक एआई केंद्र के रूप में स्थापित करना शामिल है। हालाँकि, एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच एक महत्वपूर्ण मानवीय प्रश्न भी सामने आता है। आज एआई के कारण लिखना तेज और आसान हो गया है, लेकिन इससे वास्तविक रचनात्मकता का अर्थ कुछ हद तक धुंधला पड़ने लगा है। अब लोग केवल लेख की गुणवत्ता नहीं देखते, बल्कि यह भी सोचते हैं कि उसे इंसान ने लिखा है या मशीन ने। यह सच है कि एआई द्वारा तैयार सामग्री अक्सर संतुलित और प्रभावी होती है, लेकिन उसमें वह जीवंतता नहीं होती जो किसी इंसान के अनुभव, संघर्ष और भावनाओं से आती है। एआई प्रेम, पीड़ा या संवेदनाओं की भाषा तो लिख सकती है, पर उसने स्वयं कुछ महसूस नहीं किया होता। इसलिए जब ऐसी रचना किसी व्यक्ति के नाम से प्रस्तुत की जाती है, तो यह बौद्धिक नकल जैसी स्थिति भी पैदा कर सकती है। हमें यह समझना होगा कि वास्तविक सृजन केवल परिणाम नहीं, बल्कि सोचने, गलती करने, सीखने और संघर्ष करने की प्रक्रिया भी है, जिसे एआई छोटा कर देती है। फिर भी; एआई कोई दुश्मन नहीं है। यदि इसे एक ईमानदार औजार की तरह जैसे जानकारी खोजने, विश्लेषण करने या भाषा सुधारने के लिए आदि के लिए उपयोग किया जाए, तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसके माध्यम से किए गए कार्य का पूरा श्रेय स्वयं लेने लगते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि एआई सुविधा अवश्य प्रदान करती है, लेकिन वास्तविक रचनात्मकता आज भी मनुष्य के अनुभव, संघर्ष और ईमानदारी से ही जन्म लेती है।

पारदर्शिता की पहल, पर एकरूपता के अभाव में अदालतों तक पहुंचते कर्मचारी

–डॉ. सत्यवान सौरभ

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर मनमानी, सिफारिश, पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने और प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू की गई। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से कार्यस्थल आवंटित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो। यह नीति आधुनिक प्रशासनिक सोच और तकनीकी उपयोग का सकारात्मक उदाहरण है। 50 या उससे अधिक पदों वाले संवर्गों पर लागू इस व्यवस्था में 80 अंकों का योग्यता आधारित मूल्यांकन तंत्र निर्धारित किया गया है। इसमें आयु और कुल सेवा अवधि को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिससे वरिष्ठता को उचित महत्व मिल सके। सेवा अवधि को 365 दिनों से विभाजित कर अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनती है। महिला कर्मचारियों को 10 अंक, पतिदृपत्नी मामलों में 5 अंक तथा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामलों में 10 से 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जुड़े ऑनलाइन मंच के माध्यम से संचालित होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद संवर्ग सूची सार्वजनिक की जाती है और कर्मचारी एकमुश्त पासवर्ड के माध्यम से सत्यापन कर अपने पसंदीदा कार्यस्थलों का चयन करते हैं। निर्धारित समय में विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में कर्मचारी को किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। अतिरिक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाता है तथा आदेश जारी होने के निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होता है। नीति लागू होने के बाद कई विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में कमी भी आई है। ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र ने कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मंच दिया है। इससे यह विश्वास मजबूत हुआ है कि अंकीय प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक सुधार प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं। फिर भी, नीति के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सभी विभागों में समान कार्यकाल, समान समय–सारिणी और समान नियम लागू नहीं हैं। कहीं न्यूनतम कार्यकाल अलग है, कहीं अधिकतम कार्यकाल की सीमा भिन्न है, तो कहीं विशेष परिस्थितियों की परिभाषा बदल जाती है। इससे समान संवर्ग के कर्मचारियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है और नीति की मूल भावना प्रभावित होती है। ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान की पहली ही प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रारंभिक चरण में कुछ कर्मचारी किसी कारणवश बाहर रह जाते हैं, तो उनकी कार्यस्थल वरिष्ठता प्रभावित होती है और भविष्य में विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए "एक बार की अनिवार्य सहभागिता" के माध्यम से सभी कर्मचारियों को समान आधार पर लाना चाहिए। सभी विभागों में निर्धारित कार्यकाल समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष या एक स्थानांतरण अभियान से अगले अभियान तक तथा अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया जा सकता है। इससे कोई भी कर्मचारी अत्यधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहेगा और न ही किसी को अल्प अवधि में बार–बार स्थानांतरण झेलना पड़ेगा। जब भी नई नियुक्ति हो, उसे अनिवार्य रूप से अगले स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद अब तक कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे वर्तमान अभियान में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यस्थल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और मनमानी या रिश्वतखोरी के माध्यम से पारंपरिक आदेशों द्वारा कार्यस्थल प्राप्त करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। सभी विभागों में स्थानांतरण अभियान एक ही समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इससे पतिदृपत्नी प्रकरणों में निर्णय लेने में सुविधा होगी और परिवारों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि विभिन्न विभाग अलग–अलग समय पर स्थानांतरण करेंगे, तो पारिवारिक समन्वय कठिन हो जाता है। कार्यकाल की गणना करते समय वित्तीय वर्ष को एक वर्ष माना जाना चाहिए, न कि दिनों की गणना के आधार पर। कई बार स्थानांतरण अभियान वित्तीय वर्ष के मध्य में पूरा होता है और कार्यभार ग्रहण वर्ष के अंतिम चरण में होता है, जिससे कार्यकाल की गणना में एक वर्ष का अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि वित्तीय वर्ष को पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए, तो कट–ऑफ तिथि से संबंधित विवाद समाप्त हो सकते हैं। हर वर्ष एक निश्चित और पूर्व घोषित समय–सारिणी के अनुसार स्थानांतरण अभियान चलाया जाना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया नियमित और वार्षिक हो, तो कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त होगी और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा। अनियमित या विलंबित अभियान से भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। पद पुनर्संरचना या युक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान, यदि अगली भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हो, तो न्यूनतम पदों को अवरुद्ध किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अपने निवास स्थान के निकट कार्यस्थल मिलने की अधिक संभावना रहे। यदि एक बार सभी कर्मचारियों को शामिल कर व्यापक स्तर पर युक्तिकरण किया जाए, तो भविष्य में बार–बार इस प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। वर्तमान में कई कर्मचारियों के नियुक्ति आदेशों में "अनिवार्य सहभागिता" का स्पष्ट उल्लेख है, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अभियान में भाग नहीं ले पाता, तो उसकी कार्यस्थल वरिष्ठता और अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा। इस अस्पष्टता के कारण कई कर्मचारी प्रक्रिया से बाहर रह गए, जिससे असमानता और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हुई। सबसे गंभीर चिंता यह है कि ऑनलाइन नीति लागू होने के बाद भी कुछ स्थानांतरण पारंपरिक माध्यम से किए गए हैं। यह स्थिति नीति की पारदर्शिता और निष्पक्षता के विपरीत है। जब कुछ कर्मचारियों को अंकीय आधार पर और कुछ को पारंपरिक आदेशों से कार्यस्थल दिए जाते हैं, तो समान अवसर का सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। ऐसी समानांतर व्यवस्था नीति को संदेह के दायरे में लाती है और कर्मचारियों के बीच भेदभाव की भावना उत्पन्न करती है। इन्हीं विसंगतियों के कारण अनेक कर्मचारी न्यायालयों की शरण लेने को विवश हो रहे हैं। समान पद और समान सेवा अवधि के बावजूद अलग–अलग व्यवहार से विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। न्यायालयी प्रक्रिया कर्मचारियों के लिए मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कठिन होती है, साथ ही प्रशासन पर भी अतिरिक्त बोझ डालती है। यदि नीति को पूर्णतः एकरूप और अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, सभी कर्मचारियों की एकमुश्त सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा पारंपरिक स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, तो न्यायालयों में जाने की आवश्यकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। इससे कर्मचारियों का विश्वास मजबूत होगा और प्रशासनिक प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ेगी। आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति एक दूरदर्शी पहल है, परंतु इसकी सफलता पूर्ण पारदर्शिता, समान नियम और कठोर अनुपालन पर निर्भर करती है। जब तक सभी विभागों में समान कार्यकाल, समान वार्षिक कार्यक्रम, अनिवार्य सहभागिता और केवल ऑनलाइन माध्यम से ही कार्यस्थल आवंटन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक इसकी मूल भावना अधूरी रहेगी। आज आवश्यकता है कि इस नीति को और अधिक स्पष्ट, सशक्त और एकरूप बनाया जाए। यदि ऐसा किया जाता है, तो यह व्यवस्था न केवल हरियाणा में, बल्कि पूरे देश में सुशासन, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासन का आदर्श उदाहरण बन सकती है।

अमरीका का ट्रम्प कार्ड और पाकिस्तान की छटपटाहट

–ऋतुपर्ण दवे

अगर कहा जाए कि मौजूदा अमरीका के पास 'ट्रम्प कार्ड' है जो कब चल दे, कोई नहीं जानता, तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का तल्खी भरा कहें या दर्द भरा बयान यही बताता है। गत दिवस वह नैशनल असैंबली में अमरीका की पाकिस्तान के प्रति भूमिका पर बोलते समय कुछ ऐसा बोल गए, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरी दुनिया में है। उन्होंने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान का अपने सामरिक हितों के लिए हमेशा इस्तेमाल किया, उसके बाद टॉयलैट के पेपर जैसा छोड़ दिया। निश्चित रूप से इतना तो समझ आता है कि भारत के साथ हुई ट्रेड डील के बाद पाकिस्तान में बेचौनी जरूर दिख रही थी। अन्दरूनी तौर पर पाकिस्तान इतना घबराया हुआ और परेशान होगा, यह लगता नहीं था। अमरीका ने इस्लाम को इस्लाम के खिलाफ खड़ा कर अपना मतलब साध लिया और स्वार्थी पाकिस्तान समझते हुए भी अनजान बना रहा। जब भारत से अमरीका की चंद दिनों पहले की नजदीकी समझ आई तो दर्द छलकने लगा। पाकिस्तान अच्छे से समझता था कि अफगानिस्तान की जमीन पर लड़े गए दो युद्ध न तो इस्लाम के हित में थे न ही मजहब से प्यार करने वालों के। हकीकत में ये दुनिया का दारोगा कहलाने वाले अमरीका के स्वार्थ से जुड़े थे, जो वास्तव में एक सुपरपावर की रणनीतिक जंग थी। निश्चित रूप से अब लगने लगा है कि पाकिस्तान–अमरीका के बीच मुनीर और शहबाज शरीफ के चापलूसी भरे रिश्ते पर भी अमरीकी राष्ट्रपति का ट्रम्प कार्ड चल गया है। खिसियाए पाकिस्तान और उसके रक्षा मंत्री के बयान के बाद, अब अंतर्राष्ट्रीय मायने चाहे जो निकाले जाएं लेकिन यह समझ आने लगा है कि पाकिस्तान की स्थिति 'उगलत लीलत पीर घनेरी' जैसी हो गई है, जाए तो जाए कहां? हालांकि ख्वाजा आसिफ अब मानते हैं कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ के खिलाफ और 2001 के बाद अमरीका के नेतृत्व वाले युद्धों में भाग लिया था जो धार्मिक जेहाद कतई नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह राजनीतिक लाभ और दुनिया की बड़ी शक्तियों का समर्थन प्राप्त करने बाबत था। आर्थिक रूप से टूट चुके और एक तरह से आंतरिक युद्ध के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान को पहले ही समझना था कि ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। बहरहाल मौजूदा दौर में पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ट्रम्प की चापलूसी कर–कर के बनाए गए संबंधों में न केवल कड़वाहट आ रही, बल्कि कीड़े भी पड़ रहे हैं। शायद पाकिस्तान यह भूल गया है कि अच्छा पड़ोसी उसका सही हितैषी होता है। लेकिन उसने तो शुरू से भारत को अपना दुश्मन मान रखा था, जिसके नतीजे अब दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान खुद ही अपने बुने जाल में फंस कर कैसे फडफड़ा रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट इसी से समझ आती है कि उसके मौजूदा हुक्मरान खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। अब आसिफ द्वारा की गई आलोचना उनकी छाती पीटने वाली मानसिक स्थिति जैसी है। वे इतने परेशान और व्यग्र हैं कि पूर्व सेना प्रमुखों जनरल जिया–उल–हक और परवेज मुशर्रफ की खुलकर आलोचना करते हुए यह कहने से भी नहीं हिचकते कि दोनों ने अमरीका को अफगानिस्तान युद्ध के लिए अपना पोर्ट और एयरस्पेस देकर दोगलई की। दोनों ने इस लड़ाई की खातिर अपनी रीति–नीति भी बदल दी, जिसे आज पाकिस्तान भुगत रहा है। अब आसिफ को अफगानिस्तान की तबाही याद आने के साथ–साथ खुद की गलतियां भी नजर आने लगी हैं, जिसके चलते न केवल लाखों लोग प्रभावित हुए, तबाह हुए, बल्कि पीढियां भी बर्बाद हुईं। वे इसे पाकिस्तान का 'यूज एंड थ्रो' बताते हुए यहां तक कहते हैं कि हकीकत में यह किराए का एक युद्ध था, जिसमें पाकिस्तान का अमरीका ने अपने सामरिक हितों के लिए खासा इस्तेमाल किया और मतलब निकलते ही छोड़ दिया। यकीनन टुकड़े फैंक कर पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। क्या यह सब भारत के साथ हुई डील के बाद पाकिस्तान को समझ आया? पाकिस्तान जब झोली लेकर भीख मांगते हुए अमरीका के सामने खड़ा होता था, तब यह पुरानी बातें याद क्यों नहीं रहती थीं? जब तक उसकी झोली में अमरीकी डॉलर बतौर भीख आते रहे तो मुंह बंद रहता था। तब भी क्या पाकिस्तान इतना अनजान था? अमरीका की भारत के प्रति नरमी कहें या नए व्यावसायिक क्षेत्र में साथ आने का इशारा, उससे भी पाकिस्तान परेशान है। इधर अमरीका ने दक्षिण एशिया और पश्चिमी इंडो–पैसिफिक क्षेत्र, जो ड्क्षहद महासागर और प्रशांत महासागर को जोडने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री और भू–राजनीतिक क्षेत्र है और अफ्रीका के पूर्वी तट से अमरीका के पश्चिमी तट तक फैला है, को लेकर जैसे ही भारत को भरोसेमंद सहयोगी बताया, पाकिस्तान को मानो सांप सूंघ गया। पाकिस्तान को डर क्यों लगा क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग और 65 प्रतिशत आबादी वाला क्षेत्र है।

आज से शुरु होंगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं, 53 लाख से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

8033 केन्द्रों पर आयोजित होगी परीक्षा, नकलविहीन परीक्षा का लिया संकल्प
योगी सरकार ने की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कड़े सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था
प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वॉयस रिकॉर्डरयुक्त दो सीसीटीवी कैमरों को किया गया इंस्टॉल

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी से 12 मार्च, 2026 तक आयोजित की जाएंगी। इस वर्ष कुल 53,37,778 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं, जिनमें हाईस्कूल के 27,61,696 और इंटरमीडिएट के 25,76,082 छात्र–छात्राएं शामिल हैं। परीक्षाओं को पूर्णतः नकलविहीन, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रदेश में कुल 8033 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं, जिनमें 596 राजकीय, 3453 अशासकीय सहायता प्राप्त और 3984 स्ववित्त पोषित विद्यालय शामिल हैं।

राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का शुभारंभ

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी ने परीक्षा से पूर्व मंगलवार को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), लखनऊ शिविर कार्यालय में स्थापित राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस वर्ष परीक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी बनाया गया है। 18 जनपदों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जबकि 222 परीक्षा केन्द्रों को अति संवेदनशील और 683 को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इन केन्द्रों पर एसटीएफ और स्थानीय अभिसूचना इकाई को पूरी परीक्षा अवधि में सक्रिय रखा जाएगा तथा अति संवेदनशील केन्द्रों का दिन में दो बार निरीक्षण सुनिश्चित किया गया है।

हर कक्ष में सीसीटीवी और लाइव वेबकास्टिंग

परीक्षा की निगरानी के लिए प्रत्येक परीक्षा कक्ष में वॉयस रिकॉर्डरयुक्त दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके साथ राउटर, डीवीआर और हाई–स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सम्पूर्ण परीक्षा अवधि की लाइव मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग के माध्यम से की जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम 24×7 सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे। इसके अतिरिक्त सभी 75 जनपदों के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के स्ट्रांग रूम, प्रश्नपत्र वितरण कक्ष और उत्तर पुस्तिका सीलिंग–पैकिंग कक्ष की भी ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी।

राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति

व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए 8033 केन्द्र व्यवस्थापक, 8033 बाह्य केन्द्र व्यवस्थापक, 8033 स्टैटिक मजिस्ट्रेट, 1210 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 427 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही 69 मंडलीय और 440 जनपदीय सचल दल गठित किए गए हैं। शासन स्तर से सभी 75

जनपदों और 18 मंडलों के लिए राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति भी की गई है, ताकि परीक्षा संचालन में किसी प्रकार की शिथिलता न रहे।

लखनऊ से लेकर क्षेत्रीय कार्यालयों तक कंट्रोल सेंटर

परीक्षार्थियों और अभिभावकों की सहायता के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम, लखनऊ में टोल–फ्री हेल्पलाइन नंबर 18001806607 एवं 18001806608 जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के टोल–फ्री नंबर 18001805310 एवं 18001805312 भी सक्रिय रहेंगे। ईमेल, फेसबुक, एक्स हैंडल और व्हाट्सएप के माध्यम से भी शिकायत एवं सुझाव दर्ज कराए जा सकेंगे। प्रयागराज मुख्यालय के साथ–साथ वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर के क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं।

नकल रोकने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध

नकल रोकने के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आकस्मिक स्थिति के लिए सभी विषयों के अतिरिक्त रिजर्व प्रश्नपत्र सेट डबल लॉक अलमारी में सुरक्षित रखे गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में चार रंगों में क्रमांक, परिषद का लोगो तथा सूक्ष्म "न्व्डैच" अंकन सहित विशेष सुरक्षा फीचर जोड़े गए हैं, जिससे अदला–बदली की संभावना समाप्त हो सके। इस वर्ष पहली बार यूपी संस्कृत शिक्षा परिषद की परीक्षा की भी ऑनलाइन मॉनीटरिंग की जाएगी।

अनुचित क्रियाकलाप पर होगा सख्त एक्शन

प्रदेश में लागू 'उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024' के तहत प्रश्नपत्र निर्माण, मुद्रण, वितरण, मूल्यांकन आदि में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार युवाओं के भविष्य के साथ अन्याय है और सरकार ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए अपील की कि वे बिना तनाव और भय के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दें तथा इसे एक सकारात्मक अवसर के रूप में लें। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (बेसिक और माध्यमिक शिक्षा) पार्थ सारथी सेन शर्मा, सचिव, माध्यमिक शिक्षा चन्द्र भूषण सिंह, महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा उमेश चन्द्र और शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) डॉ महेन्द्र देव उपस्थित रहे।

प्रौद्योगिकी से सशक्त एमएसएमई

योगी सरकार ने यूपी को बनाया डिजिटल औद्योगिक शक्ति केंद्र
नई एमएसएमई नीति और प्लग एंड प्ले मॉडल से निवेश को गति

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रौद्योगिकी से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बहुस्तरीय पहल की गति तेज कर दी हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी उन्नयन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से प्रदेश के 96 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को प्रतिस्पर्धी

और बाजारोन्मुख बनाने का प्रयास किया गया है। योगी सरकार के इन कदमों से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और रोजगार सृजन को नई गति प्राप्त हुई है। डिजिटल अवसंरचना, नीतिगत सरलता और वित्तीय सहयोग के संयोजन ने प्रदेश को अग्रणी औद्योगिक केंद्र बनाने की आधारभूमि को तैयार करने का काम किया है। एमएसएमई सेक्टर की योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार के बजट 2026–27 में 3,822 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जो वर्ष 2025–2026 की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना अंतर्गत मार्केटिंग डेवलपमेंट, टूलकिट वितरण और प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। एससी–एसटी और ओबीसी वर्ग के कारीगरों को तकनीक आधारित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पारंपरिक उत्पादों को ई–कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग से जोड़ने से स्थानीय वस्तुओं की पहुंच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक बढ़ी है।एमएसएमई चौम्पियनशिप इनीशिएटिव चौंपियंस पोर्टल के अंतर्गत चयनित इकाइयों को आधुनिक मशीनरी को अपनाने, गुणवत्ता सुधार और डिजिटल टूल्स के उपयोग के लिए तकनीकी सहायता दी जा रही है। उद्देश्य उत्पादन लागत को घटाकर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को और विकसित करना है। लाखों इकाइयों को डिजिटल उन्नयन और विपणन सहयोग का लाभ मिल रहा है।उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरीव2021 को लॉन्च की गई उद्यम सारथी ऐप के जरिए डिजिटल रजिस्ट्रेशन, योजनाओं की जानकारी और संचालन मार्गदर्शन एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इससे उद्यमियों की सरकारी योजनाओं और प्रोत्साहनों तक त्वरित पहुंच प्राप्त हो जाती है। आरएएमपी राइजिंग एंड एक्सेलेरेटिंग एमएसएमई परफार्मेंस योजना विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय पहल है, वित्तीय और तकनीकी समर्थन भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे इकाइयों के विस्तार आधुनिकीकरण को बल मिला है। 2022 से लागू एमएसएमई नीति के माध्यम से प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। प्लग एंड प्ले मॉडल से 72 घंटे में संचालन शुरू करने की सुविधा दी गई है। क्रेडिट प्रवाह में वृद्धि और पांच लाख रुपये तक बीमा कवरेज जैसी व्यवस्थाओं ने उद्यमियों को जोखिम प्रबंधन में सहूलियत प्रदान करने का काम किया है।

बिजली बिल राहत योजना में तेजी लायें- प्रबन्ध निदेशक

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश के विद्युत निगमों की समीक्षा बैठक में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार ने विद्युत बिल वसूली और बिजली बिल राहत योजना में तेजी लाने के लिये अधिकारियों के जमकर पेंच कसे। उन्होंने कहा कि विद्युत व्यवस्था के लिये जरूरी है कि जितनी बिजली दें उतना राजस्व वसूलें। प्रबन्ध निदेशक ने निर्देशित किया कि जहॉ भी बिजली बिल राहत योजना में प्रगति सही नहीं है वहॉ कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देशित किया कि नेवर पेड के मामले में जहॉ 50 प्रतिशत से कम रजिस्ट्रेशन है वहॉ सभी से स्पष्टीकरण मांगा जाये। प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि बिजली बिल राहत योजना में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इसमें एक–एक बकायेदार उपभोक्ता को ढूढकर पैसा जमा कराइये। पंकज कुमार ने कहा कि जहॉ भी फीडर घाटे में है वहॉ अभियान चलाकर व्यवस्था सुधारिये। इसमें लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। प्रबन्ध निदेशक ने कहा है कि विगत 1 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रारम्भ हुयी बिजली बिल राहत योजना को उपभोक्ताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। लगभग 44.5 लाख उपभोक्ताओं से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को ध्4934 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है . लेकिन अभी और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं से सम्पर्क कर बकाया जमा करायें। उसे फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी उससे सम्पर्क करके उसे योजना का लाभ लेने के लिये सहमत करें। प्रबन्ध निदेशक ने निर्देशित किया कि प्रदेश में जहॉ भी चोरी के प्रकरण में कम रजिस्ट्रेशन हुआ है उन पर कार्यवाई करिये। इसी तरह कलेक्शन इफीशियन्सी जहॉ 70 प्रतिशत से कम है वहॉ कार्यवाई होनी चाहिए। 5 किलोवाट से ऊपर के उपभोक्ताओं से सम्पर्क करिये। उनका बकाया जमा कराइये। प्रबन्ध निदेशक ने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपना विद्युत बकाया इस योजना का लाभ लेकर जमा कर दें। विद्युत दुर्धटनाओं पर उ0प्र0 पावर कारोरेशन के प्रबन्ध निदेशक पंकज कुमार ने सख्त रूख अख्तियार करते हुये कहा कि विद्युत दुर्धटनायें रोकनी हैं इसके लिये जीरों टालरेन्स की नीति है। बिना सुरक्षा उपकरण पहनें कोई भी अनुरक्षण कार्य नहीं कराया जाये। यदि कहीं भी दुर्धटना होगी तो सख्त कार्यवाही होगी। उन्होनें कहा कि अनुरक्षण कार्यो में सुरक्षा उपकरण अनिवार्य से रूप से पहन कर कार्य करें और उसको सोशल मीडिया पर भी ड़ाले। प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि समस्त प्रकार के ट्रांसफार्मर छतिग्रसतता रूकनी चाहिए। लगातार इसके लिये प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। ट्रांसफार्मर डैमेज पर सभी डिस्कॉम कार्यवाही करें। इसमें लापरवाही बरदास्त नहीं की जायेगी। उन्होंने कहाकि विद्युत बिल वसूलने के लिये अभियान चलाइये। प्रबन्ध निदेशक ने कहाकि जहॉ भी एटीएण्डसी हानियॉ ज्यादा है वहॉ योजना बनाकर व्यवस्था सुधारें। सबस्टेशन वाइज रणनीति बना ली जाये। पंकज कुमार ने कहा कि फीडर वाइस मैनेजर के कार्यो की रेग्यूलर समीक्षा करिये। उन्होंने कहाकि निवेश मित्र, झटपट पोर्टल तथा सोलर रूफटॉप में पेन्डेन्सी की शिकायतें नहीं रहनी चाहिए

सहकार से समृद्धि : एम-पैक्स से 54 लाख किसान बने आत्मनिर्भर

योगी सरकार ने महाअभियान चलाकर सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया फसली ऋण, उन्नत बीज और उर्वरक
जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक नए खाते खोले गए, 550 करोड़ की राशि खातों में जमा हुई
ग्रामीण आबादी को औपचारिक बैंकिंग व ऋण सुविधाओं से जोड़ने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार के एम–पैक्स सदस्यता महाअभियान का व्यापक परिणाम दिख रहा है। अभियान के जरिए अब तक करीब 54 लाख किसान सहकारी ढांचे से जुड़कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़े हैं। योगी सरकार का फोकस बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (एम–पैक्स) से लोगों को जोड़कर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती वित्तीय और कृषि सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

गांवों में ऋण प्रवाह बढ़ा और छोटे किसानों को मिली सहूलियतें

योगी सरकार द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत किसानों को कम ब्याज दरों पर फसली ऋण, उन्नत गुणवत्ता के बीज और उर्वरक उपलब्ध कराए गए। इससे खेती की लागत घटाने और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के उद्देश्य से जिला सहकारी बैंकों में

दो लाख से अधिक नए खाते खोले गए हैं। इन खातों में अब तक लगभग 550 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। वहीं, सदस्यों की भागीदारी से 110 करोड़ रुपये की अंश पूंजी जुटाई गई जिसके आधार पर कुल 660 करोड़ रुपये की धनराशि सहकारी तंत्र में प्रवाहित हुई। इससे गांवों में ऋण प्रवाह बढ़ा है और छोटे किसानों को सहूलियतें आसान हुई हैं।

ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण और अन्य सेवाएं

योगी सरकार ने सहकारी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए सदस्यता प्रक्रिया को भी पूरी तरह डिजिटल किया है। अब एम–पैक्स से जुड़ने के लिए डिजिटल पोर्टल और मोबाइल आधारित पंजीकरण की सुविधा लागू कर दी गई है। इससे ग्रामीणों को घर के पास ही पंजीकरण और अन्य सेवाएं मिल रहीं हैं। देश में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एम–पैक्स का सदस्यता महाअभियान शुरू किया। यह सदस्यता महाअभियान दो चरणों में चलाया गया। पहले चरण की शुरुआत सितंबर 2023 में की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर नए सदस्य जुड़े। दूसरे चरण का शुभारंभ सितंबर 2025 में किया गया, जिसमें अभियान को और गति मिली।

क्यूआर कोड और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान से आई पारदर्शिता

सहकारी समितियों को मजबूत करना योगी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। एम–पैक्स पर डिजिटल भुगतान प्रणाली क्यूआर कोड के जरिए शुरू की गई है। क्यूआर कोड और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरु हो जाने से कैशलेस एवं पारदर्शी भुगतान व्यवस्था लागू हुई है। इससे उर्वरक वितरण में पारदर्शी एवं सुविधाजनक तरीके से वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि सहकार से समृद्धि का लक्ष्य तेजी से हासिल किया जा सके।

विधानसभा में शायरी से सियासी वार, मंत्री गुलाबो देवी का विपक्ष पर तंज, जानकर अंजान बने...

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को सवाल–जवाब के दौरान सियासी तकरार के साथ शायरी का रंग भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी (सपा) की विधायक रागिनी सोनकर ने शायरी पढ़ते हुए सरकार पर हमला बोला तो मंत्री गुलाबो देवी ने उसका जवाब दिया। रागिनी सोनकर ने एडेड स्कूलों में विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि सरकार विज्ञान के शिक्षक क्यों उपलब्ध नहीं करा पा रही है और जो प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी भर्तियां कब तक की जाएंगी। इस पर जवाब देते हुए मंत्री गुलाबो देबी ने भी शायरी के अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा, जानकर अंजान बने, ये कुछ और बात है, इनको मालूम न हो ये और बात है। सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन सागर को सुखा नहीं सकतीं। मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दौरान सपा विधायक सचिन यादव बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और महात्मा बुद्ध की शोभायात्राओं पर रोक लगाए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता का सवाल खड़ा करते हुए कहा कि शोभायात्राओं

के लिए पुलिस रजिस्टर में प्रविष्टि कराकर अनुमति दिए जाने की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी 2.0 कार्यकाल में धरना–प्रदर्शन और जुलूस आदि के लिए शासनादेश जारी किया गया है। धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं और उन्हीं के तहत अनुमति दी जाती है। सदन में विधायक पल्लवी पटेल ने उच्च शिक्षा से जुड़ा सवाल उठाया। उन्होंने विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मेडिकल लीव दिए जाने की व्यवस्था पर जानकारी मांगी। इस पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाओं का विवरण साझा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अलग–अलग प्रशासनिक इकाइयां हैं, इसलिए दोनों के शिक्षकों को मिलने वाली सुविधाएं समान हों, यह आवश्यक नहीं है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाहजहाँपुर आश्रम में श्रीराम चंद्र मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे

20 दिन के इस उत्सव को सभी धर्मों का 'महाकुंभ' माना जा रहा है

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद कल शाहजहाँपुर में हो रहे श्रीराम चंद्र मिशन आश्रम के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। आश्रम में 12 फरवरी से 2 मार्च के बीच एक विशाल स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसे आयोजनकर्ता और अनुयायी सभी धर्मों का महाकुंभ मान रहे हैं। बीस दिन के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में सामूहिक ध्यान, मनन–चर्चा और सेवा होगी। इस समारोह में सामूहिक ध्यान का नेतृत्व हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक और श्रीराम चंद्र मिशन के अध्यक्ष आदरणीय दाजी करेंगे। स्वर्ण जयंती समारोह के महत्व पर बोलते हुए हार्टफुलनेस के मार्गदर्शक और श्रीराम चंद्र मिशन के अध्यक्ष आदरणीय दाजी ने कहा, "शाहजहाँपुर आश्रम के पचास साल पूरे होना हमारे पिछले मार्गदर्शकों के निरंतर आध्यात्मिक कार्य का प्रतीक है। शाहजहाँपुर आश्रम आध्यात्मिकता की लहरें प्रसारित करने और चेतना के सामूहिक विकास के लिए दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करने का केंद्र रहा है। यह जगह मननशील जीवनचर्या, ध्यान सत्रों और सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र के तौर पर काम करती रही है।" स्वर्ण जयंती समारोह पाँच भागों में आयोजित किया जा रहा है– पहला 12–14 फरवरी के बीच, दूसरा 16–18 फरवरी के बीच, उसके बाद 20–22 फरवरी, 24–26 फरवरी के बीच और आखिरी 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच। पूरे भारत और कई अन्य देशों से हज़ारों भक्तों के आने की उम्मीद है जो मिशन की लगातार वैश्विक मौजूदगी और राज योग करने वालों के बीच इसके हमेशा बने रहने वाले आकर्षण को दिखाता है। समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। पहुँचने की सुविधा के लिए लखनऊ और नई दिल्ली के एयरपोर्ट, लखनऊ के रेलवे स्टेशन और लखनऊ और शाहजहाँपुर के बस स्टेशनों पर स्वयंसेवक तैनात किए गए हैं। यह आश्रम आंतरिक अनुशासन, सामूहिक चेतना और आध्यात्मिक सुधार के लिए प्रेरित करता है। एक आधुनिक ध्यान केंद्र और 'सहज मार्ग' के वैश्विक केंद्र के तौर पर बना यह आश्रम पाँच दशकों के अपने सफ़र में 164 देशों के सभी धर्मों के लोगों को एक साथ लाया है। इस आश्रम को इसके संस्थापक रामचंद्र महाराज ने 1976 की बसंत पंचमी पर अपने गुरु समर्थ महात्मा श्रीरामचंद्र जी महाराज की याद में समर्पित किया था।

संक्षिप्त

विपक्ष का आरोप, जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते अधिकारी

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान मंगलवार को कार्यपालिका और जनप्रतिनिधियों के संबंधों को लेकर सदन में तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने आरोप लगाया कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन तक नहीं उठाते और दलाली में व्यस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका का विधायिका पर हावी होना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने पीठ से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि सदन की गरिमा की अवहेलना हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक कमाल अखघ्तर ने भी कहा कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को भी धरने पर बैठना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी की सुनवाई नहीं करते, जिससे सभी दलों के विधायक परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे नौकरशाही पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित हो सके। सपा विधायक संग्राम सिंह यादव ने भी अधिकारियों पर फोन न उठाने और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा द्वारा जनप्रतिनिधियों के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराया जाए और किसी भी अधिकारी द्वारा उसकी अवहेलना न होने पाए। सपा विधायक रागिनी सोनकर भी अधिकारियों की कथित लापरवाही का मुद्दा उठाते हुए जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को गंभीरता से लेने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि मामला पीठ के संज्ञान में है और इस पर उचित व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री से बातचीत कर ठोस समाधान निकालने का आश्वासन दिया। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका के व्यवस्थापिका पर हावी होने का सवाल ही नहीं उठता है और जो अधिकारी जनप्रतिनिधियों के फोन नहीं उठाते, सरकार उनके साथ नहीं है। इसको लेकर पहले से जारी शासनादेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं मंत्री असीम अरुण ने सुझाव दिया कि प्रदेश या जिला स्तर पर ऐसे अधिकृत नंबर जारी किए जाएं, जिन पर हर हाल में अधिकारियों को जवाब देना अनिवार्य हो, ताकि जनप्रतिनिधियों की शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके। कई बार अधिकारियों के सामने भी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके चलते वो फोन नहीं उठाते हैं।

केरल टूरिज्म ने लॉन्च किया ऑल-इंडिया 'ट्रैवेल नाउ, पोस्ट लेटर' कैम्पेन, गर्मियों की छुट्टियों से पहले बड़े शहरों में रोड्शो का आयोजन

संवाददाता

लखनऊ। केरल टूरिज्म ने ट्रैवेल नाउ, पोस्ट लेटर नाम का एक वैश्विक अभियान शुरू किया है। यह अभियान माइंडफुल ट्रैवेल को बढ़ावा देता है और दुनिया भर के यात्रियों से अपील करता है कि वे पहले खुद अपनी आँखों और मन से उस पल को जीएँ, फिर उसे ऑनलाइन शेयर करें। इसका मुख्य आइडिया बहुत सरल और सभी के लिए एक जैसा है, पहले अनुभव करो, बाद में पोस्ट करो। यह याद दिलाता है कि सबसे खूबसूरत यात्रा की कहानियाँ पहले महसूस की जाती हैं, बताई नहीं जातीं। यात्रा में उपस्थिति सबसे पहले होनी चाहिए, परफॉर्मेंस बाद में।'ट्रैवेल नाउ, पोस्ट लेटर' के जरिए केरल टूरिज्म खुद को एक थॉट लीडर के रूप में पेश कर रहा है, जो दुनिया भर में यात्रा करने के तरीके पर एक बड़ी बातचीत शुरू कर रहा है। यह यात्रा को सिर्फ दिखावे की बजाय जागरुकता बढ़ाने, विचारों को प्रस्प्तुत करने और असली जुड़ाव का माध्यम बनाता है। ट्रैवल नाउ, पोस्ट लेटर केरल टूरिज्म का एक सोशल मीडिया कैम्पेन है, जो माइंडफुल ट्रैवेल और मौजूदगी पर आधारित अनुभवों को प्रोत्साहित करता है। यह अभियान केरल टूरिज्म के आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है। साथ ही एक खास माइक्रोसाइट भी है, 'ीजजचेरू्ध्ध् जतंअमसदवूचवेजसंजमत.बवउध्। इस वेबसाइट पर अभियान की पूरी विचारधारा, चुनिंदा कंटेंट और यात्रा को अधिक जागरूक बनाने के लिए कुछ आसान टूल्स दिए गए हैं।कोच्चि–मुजिरिस बाएनियल भारत के सबसे आकर्षक सांस्कृतिक स्थलों में से एक के रूप में विकसित हो चुका है, जिसने कोच्चि को कला–प्रेरित यात्रा के लिए एक खूबसूरत ग्लोबल डेस्टिनेशन में बदल दिया है। फोर्ट कोच्चि के ऐतिहासिक इलाकों और उसके विरासत वाले क्षेत्रों में आयोजित यह बाएनियल समकालीन कला का संयोजन जीवंत इतिहास के साथ करता है, और पर्यटकों को संस्कृति, रचनात्मकता और स्थान पर आधारित एक शानदार पर्यटन अनुभव प्रदान करता है।यह बाएनियल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समकालीन कला का आयोजन है जोकि 31 मार्च तक चलेगा। यह दुनिया भर के कलाकारों और पर्यटकों को कोच्चि आने के लिए आकर्षित करता है।

अच्छा लेखन वही जिसे समाज को लाभ मिले : डॉ. रीता बहुगुणा जोशी

बीएनई

वाराणसी। साहित्य तब सार्थक होता है जब वह समाज के काम आए, जब उसकी पंक्तियाँ केवल अलंकरण न बनें बल्कि चेतना का स्रोत बनें। अशोका इंस्टीट्यूट के बुद्ध सभागार में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत की पुस्तक 'सपनों की पगडंडियां' के विमोचन अवसर पर देश की जानी–मानी इतिहासकार एवं पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने यही बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। उन्होंने कहा कि अच्छा लेखन वही है जिसकी पुस्तकें पढ़ी जाएं और जिनसे समाज को वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने अपने संबोधन में

कहा कि जीवन का कोई भी मार्ग सरल नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष की लंबी यात्रा छिपी होती है। 'सपनों की पगडंडियां' केवल एक व्यक्ति विशेष की जीवनी नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प और शिक्षा के प्रति समर्पण की गाथा है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के जीवन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें जिज्ञासा थी, आगे बढ़ने की बेचैनी थी और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का साहस था। यही कारण है कि कठिन राहों पर चलते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। डॉ. जोशी ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए प्रोफेसर कुशवाहा ने शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना केवल शैक्षणिक निर्णय नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रयास था। कुलपति जैसे उच्च पद पर रहते हुए भी वे छात्रों के बीच जाकर कक्षाएं लेते थे। उन्होंने शिक्षा को प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम माना। उनके प्रयासों से छात्रों में आत्मविश्वास जागा और शिक्षा के प्रति नई चेतना विकसित हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बनारस की धरती सदियों से विद्वानों और विचारकों की जन्मस्थली रही है। यहां की मिट्टी में एक विशिष्ट प्रकार की बौद्धिक ऊर्जा है। विजय विनीत ने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह दिखाया है कि चेतना की यह परंपरा आज भी जीवित है। नवभारत टाइम्स लखनऊ के संपादक सुधीर मिश्रा ने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आने वाले समय में पत्रकारिता किस रूप में होगी, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। ऐसे समय में विजय विनीत ने पत्रकारिता और एआई जैसे विषयों पर गंभीर लेखन कर पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने विजय विनीत की चर्चित कृति 'मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना' का उल्लेख करते हुए कहा कि स्मृतियों को साहित्य में ढालना साधारण कार्य नहीं है। वर्षों की यादों को कहानी संग्रह में सहेजना लेखक की संवेदनशीलता का प्रमाण है। वरिष्ठ लेखक एवं रंगकर्मी व्योमेश शुक्ल ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा मूर्धन्य विद्वान हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक संरचनाओं की जकड़न के बीच भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई राह बना सकता है। उन्होंने कहा कि विजय विनीत ऐसे लेखक हैं जो किसी चरित्र को उसकी वास्तविकता में प्रस्तुत करने का साहस रखते हैं। धूल–धूसरित जीवन को उसकी संपूर्ण गरिमा के साथ सामने लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विजय विनीत केवल लेखक नहीं, बल्कि संवेदनशील और निर्भीक पत्रकार हैं। उन्होंने समय–समय पर सत्ता से सवाल किए हैं। बनारस में कोरोना काल का इतिहास उनके बिना अधूरा रहेगा। किसानों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 'सपनों की पगडंडियां' एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तक बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि संकल्प अडिग हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि विजय विनीत ने अत्यंत स्पष्ट और सादगीपूर्ण भाषा में प्रोफेसर कुशवाहा के व्यक्तित्व को उकेरा है। पुस्तक यह संदेश देती है कि सपनों की पगडंडियां अंततः सपनों के राजमहल तक ले जाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि मुकदमों और विरोध के बावजूद विजय विनीत की कलम कभी नहीं रुकी। वे सच को उसी तीखेपन और ईमानदारी से लिखते हैं, जैसा वे देखते और महसूस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पर उनका अनुभव पत्रकारिता के छात्रों के लिए उपयोगी है। वरिष्ठ साहित्यकार रामजी यादव ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा ने जरूरतमंद छात्रों की भरपूर सहायता की। उनके भीतर मानवीय गुणों की गहराई थी। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. लेनिन रघुवंशी ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा कई वर्षों तक नोबेल समिति में सलाहकार सदस्य रहे। उन्होंने कभी आडंबर का सहारा नहीं लिया। उनका जीवन प्रेम और सकारात्मक विद्रोह पर आधारित रहा। कार्यक्रम के दौरान अशोका इंस्टीट्यूट के संस्थापक अशोक कुमार मौर्य को मानवाधिकार जन निगरानी समिति की ओर से 'जनमित्र अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मानवाधिकार जन निगरानी समिति की ओर से दिया गया। इसके अलावा जाने माने पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार राम जी यादव, उद्घोषक अशोक आनंद, रणभेरी न्यूज़ की संपादक समेला आफरीन की प्रतिनिधि सुमन अग्रहरि, पत्रकार रोहित सेठ चित्रकार अमित मेहता के अलावा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्त और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह सहित अनेक साहित्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत ने

अतिथियों का परिचय कराते हुए उनका स्वागत किया। संचालन अशोक आनंद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन 'मेरा शहर' संस्था की अध्यक्ष सोनम उपाध्याय ने किया।अच्छा लेखन वही जिसे समाज को लाभ मिले रू डॉ. रीता बहुगुणा जोशी वाराणसी। साहित्य तब सार्थक होता है जब वह समाज के काम आए, जब उसकी पंक्तियाँ केवल अलंकरण न बनें बल्कि चेतना का स्रोत बनें। अशोका इंस्टीट्यूट के बुद्ध सभागार में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत की पुस्तक 'सपनों की पगडंडियां' के विमोचन अवसर पर देश की जानी–मानी इतिहासकार एवं पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी ने यही बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कही। उन्होंने कहा कि अच्छा लेखन वही है जिसकी पुस्तकें पढ़ी जाएं और जिनसे समाज को वास्तविक लाभ मिले। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जीवन का कोई भी मार्ग सरल नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे संघर्ष की लंबी यात्रा छिपी होती है। 'सपनों की पगडंडियां' केवल एक व्यक्ति विशेष की जीवनी नहीं, बल्कि संघर्ष, संकल्प और शिक्षा के प्रति समर्पण की गाथा है। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा के जीवन को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि उनमें जिज्ञासा थी, आगे बढ़ने की बेचैनी थी और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का साहस था। यही कारण है कि कठिन राहों पर चलते हुए भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। डॉ. जोशी ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय में कुलपति रहते हुए प्रोफेसर कुशवाहा ने शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना केवल शैक्षणिक निर्णय नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा का प्रयास था। कुलपति जैसे उच्च पद पर रहते हुए भी वे छात्रों के बीच जाकर कक्षाएं लेते थे। उन्होंने शिक्षा को प्रशासनिक दायित्व नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम माना। उनके प्रयासों से छात्रों में आत्मविश्वास जागा और शिक्षा के प्रति नई चेतना विकसित हुई। उन्होंने यह भी कहा कि बनारस की धरती सदियों से विद्वानों और विचारकों की जन्मस्थली रही है। यहां की मिट्टी में एक विशिष्ट प्रकार की बौद्धिक ऊर्जा है। विजय विनीत ने अपनी पुस्तक के माध्यम से यह दिखाया है कि चेतना की यह परंपरा आज भी जीवित है। नवभारत टाइम्स लखनऊ के संपादक सुधीर मिश्रा ने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आने वाले समय में पत्रकारिता किस रूप में होगी, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। ऐसे समय में विजय विनीत ने पत्रकारिता और एआई जैसे विषयों पर गंभीर लेखन कर पत्रकारों और पत्रकारिता के विद्यार्थियों को दिशा देने का काम किया है। उन्होंने विजय विनीत की चर्चित कृति 'मैं इश्क लिखूं तुम बनारस समझना' का उल्लेख करते हुए कहा कि स्मृतियों को साहित्य में ढालना साधारण कार्य नहीं है। वर्षों की यादों को कहानी संग्रह में सहेजना लेखक की संवेदनशीलता का प्रमाण है। वरिष्ठ लेखक एवं रंगकर्मी व्योमेश शुक्ल ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा मूर्धन्य विद्वान हैं। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक संरचनाओं की जकड़न के बीच भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा और परिश्रम से नई राह बना सकता है। उन्होंने कहा कि विजय विनीत ऐसे लेखक हैं जो किसी चरित्र को उसकी वास्तविकता में प्रस्तुत करने का साहस रखते हैं। धूल–धूसरित जीवन को उसकी संपूर्ण गरिमा के साथ सामने लाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर मनोज कुमार सिंह ने कहा कि विजय विनीत केवल लेखक नहीं, बल्कि संवेदनशील और निर्भीक पत्रकार हैं।

उन्होंने समय–समय पर सत्ता से सवाल किए हैं। बनारस में कोरोना काल का इतिहास उनके बिना अधूरा रहेगा। किसानों और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों के लिए 'सपनों की पगडंडियां' एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह पुस्तक बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि संकल्प अडिग हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के निवर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे ने कहा कि विजय विनीत ने अत्यंत स्पष्ट और सादगीपूर्ण भाषा में प्रोफेसर कुशवाहा के व्यक्तित्व को उकेरा है। पुस्तक यह संदेश देती है कि सपनों की पगडंडियां अंततः सपनों के राजमहल तक ले जाती हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक अभिषेक श्रीवास्तव ने कहा कि मुकदमों और विरोध के बावजूद विजय विनीत की कलम कभी नहीं रुकी। वे सच को उसी तीखेपन और ईमानदारी से लिखते हैं, जैसा वे देखते और महसूस करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषय पर उनका अनुभव पत्रकारिता के छात्रों के लिए उपयोगी है। वरिष्ठ साहित्यकार रामजी यादव ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा ने जरूरतमंद छात्रों की भरपूर सहायता की। उनके भीतर मानवीय गुणों की गहराई थी। सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. लेनिन रघुवंशी ने कहा कि प्रोफेसर कुशवाहा कई वर्षों तक नोबेल समिति में सलाहकार सदस्य रहे। उन्होंने कभी आडंबर का सहारा नहीं लिया। उनका जीवन प्रेम और सकारात्मक विद्रोह पर आधारित रहा। कार्यक्रम के दौरान अशोका इंस्टीट्यूट के संस्थापक अशोक कुमार मौर्य को मानवाधिकार जन निगरानी समिति की ओर से 'जनमित्र अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान मानवाधिकार जन निगरानी समिति की ओर से दिया गया। इसके अलावा जाने माने पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार राम जी यादव, उद्घोषक अशोक आनंद, रणभेरी न्यूज़ की संपादक समेला आफरीन की प्रतिनिधि सुमन अग्रहरि, पत्रकार रोहित सेठ चित्रकार अमित मेहता के अलावा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी प्रसाद गुप्त और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह सहित अनेक साहित्यकारों, पत्रकारों और कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विजय विनीत ने अतिथियों का परिचय कराते हुए उनका स्वागत किया। संचालन अशोक आनंद ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन 'मेरा शहर' संस्था की अध्यक्ष सोनम उपाध्याय ने किया।

दुद्धी विकास खंड के छात्रों ने हिण्डाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किया शैक्षिणिक भ्रमण

बीएनई

रेणुकूट (सोनभद्र)। दुद्धी विकास खंड के शिक्षाधिकारी प्रेम शंकर राम के नेतृत्व में कक्षा 6 से 8 के तकरीबन 100 छात्र–छात्राओं ने हिण्डाल्को के ट्रेनिंग सेंटर– "हिण्डाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस" का एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण किया। जिसका उद्देश्य कौशल विकास और आधुनिक तकनीकी ज्ञान को बढ़ाना था। बच्चों को आधुनिक तकनीकियों में निपुण बनाना और रोजगारपरक शिक्षा के लिए अभी से तैयार करने के उद्देश्य से कार्यशाला के दौरान दुद्धी विकास खंड के छात्र–छात्राओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्लांट की मशीनों के संचालन व उत्पादन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न पहलुओं पर गहन जानकारी और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। भ्रमण के दौरान छात्र–छात्राओं को अत्याधुनिक लैब में आधुनिक तकनीकी ज्ञान से परिचित कराया गया। हिण्डाल्को स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस की उपमहाप्रबंधक सोनाली साओ, सहायक प्रबंधक सूरज दास, डिप्टी मैनेजर सेबेस्टियन जोश व अन्य ने हिण्डाल्को की विशेषज्ञ टीम के साथ मिलकर छात्रों को सुरक्षा, नवीन तकनीकों और औद्योगिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर हिण्डाल्को जनसंपर्क एवं प्रशासनिक विभाग के महाप्रबंधक यशवंत कुमार, जनसम्पर्क अधिकारी प्रशान्त श्रीवास्तव, हिण्डाल्को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की अस्मिता प्रजापति व प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर दुद्धी विकास खंड

के शिक्षाधिकारी प्रेम शंकर राम ने कहा कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के निर्देश के क्रम में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत बच्चों की परीक्षा कराई गई थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण सुपर 100 बच्चों के शैक्षणिक विजिट का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि हिण्डाल्को एवं दुद्धी विकासखंड के इस संयुक्त प्रयास से छात्रों को न केवल तकनीकी कौशल प्राप्त होगा, बल्कि उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यह कार्यशाला और भ्रमण छात्रों के लिए आधुनिक तकनीकों को समझने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का सुनहरा अवसर साबित हुआ है। इस आयोजन ने छात्रों को नवाचार और आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस करने के साथ–साथ उनकी व्यावसायिक सफलता की संभावनाओं को मजबूत किया है। उन्होंने इस आयोजन पर हिण्डाल्को प्रबंधन एवं जिला बेसिक शिक्षाधिकारी मुकुल आनंद पांडेय का भी धन्यवाद ज्ञापित किया।

महिला स्वास्थ्य और सशक्तिकरण की दिशा में एनसीएल की सार्थक पहल

एनसीएल की सीएसआर पहल से 'पाखी' सैनिटरी पैड का उत्पादन और आपूर्ति

बीएनई

सिंगरौली। महिला स्वास्थ्य एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एनसीएल ने सोमवार को एनसीएल ने अवंतीबाई स्वयं सहायता समूह, पीपरखड़ के साथ एमओयू किया।

इस एमओयू के तहत एनसीएल द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत सिंगरौली एवं सोनभद्र के 28 विद्यालयों में तीन वर्ष की अवधि तक 'पाखी' सैनिटरी पैड की निःशुल्क नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा। एनसीएल की इस पहल से लगभग 8,000 छात्राओं को मासिक धर्म स्वच्छता का लाभ मिलेगा एवं स्थानीय महिलाओं को रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे।

इस अवसर पर एनसीएल की ओर से महाप्रबंधक (सीएसआर), राजीव रंजन और अवंतीबाई स्वयं सहायता समूह, पीपरखड़ की ओर से सचिव, उर्वशी रानी सिंह वैश ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पीपरखड़ स्थित श्पाखीश सैनिटरी पैड निर्माण इकाई की स्थापना एनसीएल झिंगुरदा द्वारा आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी के सहयोग से की गई है। इस इकाई का संचालन आजीविका मिशन के अंतर्गत अवंती बाई स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कर रही हैं, जहाँ उन्हें सेनेटरी पैड बनाने का प्रशिक्षण के साथ मासिक धर्म एवं उससे जुड़े मिथ्यो के प्रति जागरूक किया जाता है । इस केन्द्र के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार, कौशल विकास एवं आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

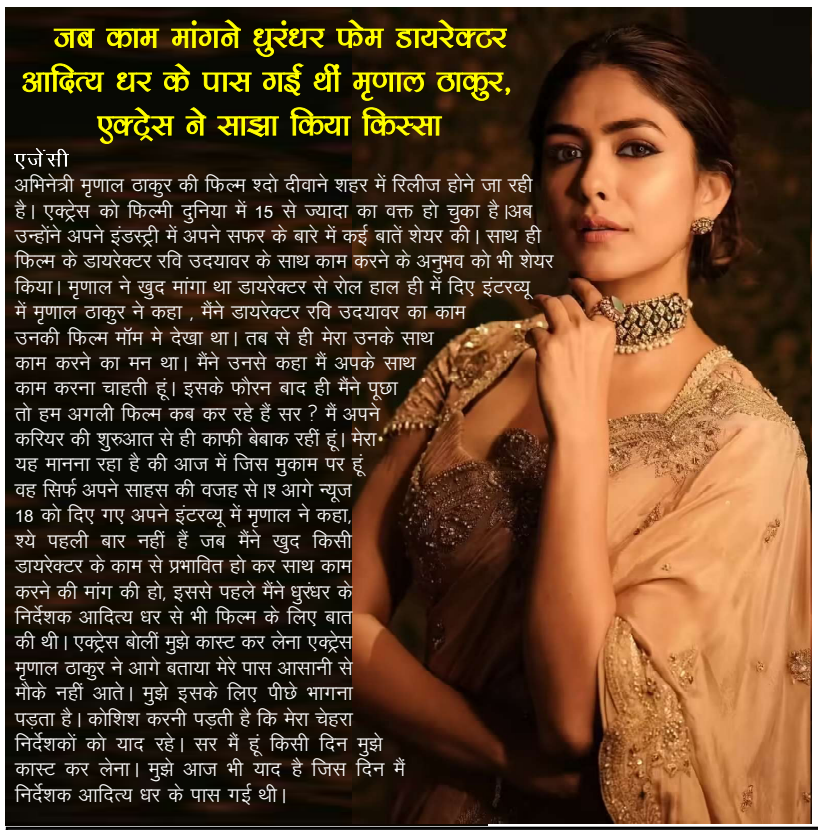

एजेंसी

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की फिल्म श्दो दीवाने शहर में रिलीज होने जा रही है। एक्ट्रेस को फिल्मी दुनिया में 15 से ज्यादा का वक्त हो चुका है।अब उन्होंने अपने इंडस्ट्री में अपने सफर के बारे में कई बातें शेयर की। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर रवि उदयावर के साथ काम करने के अनुभव को भी शेयर किया। मृणाल ने खुद मांगा था डायरेक्टर से रोल हाल ही में दिए इंटरव्यू में मृणाल ठाकुर ने कहा , मैंने डायरेक्टर रवि उदयावर का काम उनकी फिल्म मॉम मे देखा था। तब से ही मेरा उनके साथ काम करने का मन था। मैंने उनसे कहा मैं अपके साथ काम करना चाहती हूं। इसके फौरन बाद ही मैंने पूछा तो हम अगली फिल्म कब कर रहे हैं सर ? मैं अपने करियर की शुरुआत से ही काफी बेबाक रहीं हूं। मेरा• यह मानना रहा है की आज में जिस मुकाम पर हूं वह सिर्फ अपने साहस की वजह से।श आगे न्यूज 18 को दिए गए अपने इंटरव्यू में मृणाल ने कहा, श्ये पहली बार नहीं हैं जब मैंने खुद किसी डायरेक्टर के काम से प्रभावित हो कर साथ काम करने की मांग की हो, इससे पहले मैंने धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर से भी फिल्म के लिए बात की थी। एक्ट्रेस बोलीं मुझे कास्ट कर लेना एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने आगे बताया मेरे पास आसानी से मौके नहीं आते। मुझे इसके लिए पीछे भागना पड़ता है। कोशिश करनी पड़ती है कि मेरा चेहरा निर्देशकों को याद रहे। सर मैं हूं किसी दिन मुझे कास्ट कर लेना। मुझे आज भी याद है जिस दिन मैं निर्देशक आदित्य धर के पास गई थी।

सिर्फ एक तकनीक नहीं, पूरी कहानी गढ़ रहे हैं देश

एनवीडिया और मोजिला के दिग्गज क्या बोले जानिए सबकुछ

दिल्ली ब्यूरो

नई दिल्ली। वैश्विक तकनीकी पटल पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दुनिया भर के देश अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एक तकनीक या टूल के रूप में नहीं देख रहे, बल्कि इसे अपनी संप्रभुता और सामरिक रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। एनवीडिया की वीपी सोवेरन एआई कैलिस्टा रेडमंड ने सोमवार को श्एआई इंडिया इम्पैक्ट समिटश में यह अहम बात कही। उन्होंने साफ किया कि भारत समेत दुनिया के देश अब एआई के किसी एक घटक पर नहीं, बल्कि इसकी पूरी कहानी और बुनियादी ढांचे पर फोकस कर रहे हैं। यह बदलाव भारत जैसे देशों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी खुद की एआई क्षमताओं को विकसित करने की दौड़ में शामिल हैं। हार्डवेयर से लेकर मॉडल्स तक सम्मेलन में बोलते हुए रेडमंड ने कहा कि जब वह वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों से बात करती हैं, तो एक स्पष्ट ट्रेंड दिखाई देता है– राष्ट्र श्लॉन्च गेमश (लंबी पारी) खेलने की तैयारी में हैं। वे केवल पहली रिलीज या किसी एक एप्लिकेशन के सफल होने का इंतजार नहीं कर रहे। इसके बजाय, उनकी नजर पूरे टेक्नोलॉजी स्टैक पर है। रेडमंड ने बताया कि सरकारें अब हार्डवेयर, फाउंडेशनल मॉडल्स और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने पर जोर दे रही हैं जो बेहतरीन एप्लिकेशंस बनाने के लिए जरूरी है। यह दृष्टिकोण केवल सॉफ्टवेयर खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि घरेलू स्तर पर डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसे ही श्सोवेरन एआईश का नाम दिया गया है, जिसमें स्थानीय टीमों द्वारा स्थानीय डेटासेट पर प्रशिक्षित लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स शामिल हैं। ओपन सोर्सरू संप्रभुता की चाबी समिट के दौरान टेक लीडर्स ने श्ओपन सोर्स एआईश की भूमिका पर भी गहन चर्चा की। मोजिला के अध्यक्ष मार्क सुरमन ने इस बात पर जोर दिया कि एआई का केंद्रीकरण किसी भी देश की डिजिटल संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सुरमन के अनुसार, ओपन वेब और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी इस खतरे का जवाब हैं।

उन्होंने कहा कि ओपन सोर्स की मूल भावना यही है कि कोई भी,

कहीं भी, अपनी शर्तों पर तकनीक का निर्माण कर सके। हालांकि इसमें अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन यह तकनीक को इस तरह डिजाइन करने की आजादी देता है जिससे देशों को अपनी संप्रभुता बनाए रखने का बेहतर मौका मिलता है। रेडमंड ने भी माना कि दशकों से ओपन सोर्स एक श्ग्रेट लेवलरश (समान अवसर प्रदान करने वाला) रहा है। भारत का एआई मिशनरू आत्मनिर्भरता की ओर कदम भारत सरकार की रणनीतियां रेडमंड के इन विचारों से पूरी तरह मेल खाती हैं। भारत का श्इंडिया एआई मिशनश एक व्यापक इकोसिस्टम बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, डेटा की गुणवत्ता बढ़ाना और स्वदेशी एआई क्षमताओं को विकसित करना है। इस साल के समिट की एक बड़ी उपलब्धि उन 12 भारतीय स्टार्टअप्स की प्रगति रही, जिन्हें इंडिया एआई मिशन के तहत चुना गया है। ये स्टार्टअप्स भारतीय डेटासेट और भाषाओं पर प्रशिक्षित स्वदेशी फाउंडेशन मॉडल विकसित कर रहे हैं। इनका लक्ष्य भारत की भाषाई विविधता और विशिष्ट क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करना है, जो पश्चिमी एआई मॉडल्स अक्सर नहीं कर पाते। आगे की राहरू परिणामों पर फोकस सोमवार को शुरू हुए इस समिट का मुख्य फोकस सिर्फ चर्चाओं पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर है। नीति निर्माताओं और उद्योग के दिग्गजों का मानना है कि एआई इकोसिस्टम का उपयोग दक्षता बढ़ाने, उत्पादकता में सुधार करने और अर्थव्यवस्था के लिए एक श्मल्टीप्लायर इफेक्टश (गुणात्मक प्रभाव) पैदा करने में किया जाना चाहिए। रेडमंड का यह बयान कि ष्देश एआई की पूरी कहानी देख रहे हैं,ष यह दर्शाता है कि एआई अब केवल आईटी विभाग का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह राष्ट्रीय एजेंडा का एक मुख्य हिस्सा बन चुका है। भारत जैसे देशों के लिए, जो अपनी आबादी के लिए समावेशी समाधान बनाना चाहते हैं, यह श्संप्रभु एआईश ही भविष्य का रास्ता है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743